

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 332 बेमेतरा, मंगलवार 28 जुलाई 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 1 रुपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर सोते पति का घोंटा गला; वारदात के बाद दोनों फरार

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में अवैध संबंधों के चलते एक के बाद एक खौफनाक वारदातों का सिलसिला जारी है। हाल ही में मेरठ में पति को सांप से डसवाकर मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया था, और अब जौनपुर में भी प्रेम प्रसंग के चलते एक पति को अपनी जान गंवानी पड़ी है। यहां बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के भलुआही वार्ड संख्या आठ में शुक्रवार की रात एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सोते हुए पति की गला घोटकर निर्मम हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। मृतक के पिता लालजी गौतम द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, उनका 27 वर्षीय बेटा चंद्रदीप शुक्रवार रात रोज की तरह खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया था। रात करीब 11 बजे के बाद उसकी पत्नी वंदना ने अपने मायके (बदलापुर के गजाधरपुर निवासी) के प्रेमी राजेश कुमार को घर बुला लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर गहरी नींद में सो रहे चंद्रदीप के गले में गमछा कसकर उसका दम घोंट दिया। हत्या की इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पत्नी अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर फरार हो गईं।

ग्रेटर नोएडा में क्रिकेट खेलते समय गड्डे में गिरने से 6 वर्षीय मासूम की मौत

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में प्रशासनिक लापरवाही के कारण एक बेहद दुःखद घटना सामने आई है। नॉलेज पार्क क्षेत्र की कलाधाम सोसायटी के पास शनिवार शाम को क्रिकेट खेलते समय बोरिंग के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चों के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक बालक अत्यान सूर्या पुत्र सोवान यादव हैं। अत्यान शनिवार को सोसायटी के बाहर अन्य बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। खेलते-खेलते वह अचानक वहां खोदे गए एक 15 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया।

लोक परीक्षा विधेयक,2026 पर खत्म हुआ गतिरोध

संसद में आज एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा और वोटिंग

नई दिल्ली / एजेंसी

संसद में सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर जारी गतिरोध अब खत्म होने के आसार हैं। सूत्रों के अनुसार, सभी प्रमुख राजनीतिक दल मंगलवार, 28 जुलाई को विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए सहमत हो गए हैं। इससे पहले विपक्षी सदस्यों के हंगामे और विरोध के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सार्वजनिक परीक्षा विधेयक पर व्यापक चर्चा के लिए छह घंटे का विशेष समय देने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि, देश की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सभी

दलों का एकजुट दृष्टिकोण जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक, ओम बिरला ने विभिन्न राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं के साथ लगातार बातचीत की। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मंगलवार को विधेयक पर विस्तृत चर्चा कराने को लेकर सहमति बनी। यह विधेयक देशभर में हृष्यध्वज-त पेपर लीक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में लाया गया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल, संगठित परीक्षा माफिया और अन्य अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में पेश किया था। संशोधन विधेयक में व्यक्तिगत अपराधों के लिए सजा को मौजूदा अधिकतम पांच वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक करने का



प्रस्ताव है। इसके साथ ही 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संगठित अपराध के मामलों में न्यूनतम सजा को मौजूदा पांच वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष करने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में जुर्माने की अधिकतम सीमा

10 करोड़ तक करने की बात कही गई है। इसके अलावा, कानून के तहत आने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने का भी प्रस्ताव है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने भी विपक्षी नेताओं से

विधेयक पर चर्चा की अनुमति देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर चर्चा के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है। रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि सभी सदस्य चर्चा के लिए तैयार होकर आए हैं और कई विपक्षी सांसदों ने संशोधन भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक छात्रों और युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है और सभी दलों को इस पर चर्चा करनी चाहिए। स्पीकर की इस सकारात्मक पहल के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स से लोकसभा अध्यक्ष ने खुद बातचीत की। इसके परिणामस्वरूप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सहमति बनाते हुए मंगलवार को विधेयक पर विस्तृत चर्चा कराने का फैसला लिया। इससे सदन में सहमति और संवाद की भावना को भी बल मिला है।

मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, एसी रुम का एक्टिविस्ट नहीं इस्तीफे के बाद धर्मेन्द्र प्रधान का पहला बयान

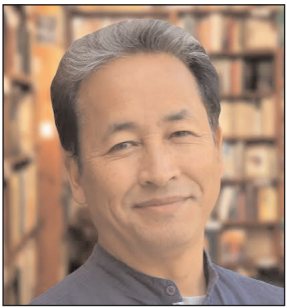
इस्तीफे के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का पहला रिक्वेशन आया है। धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि वो स्ट्रीट फाइटर हैं, वो एसी रुम में बैठने वाले एक्टिविस्ट नहीं हैं। दरअसल, संसद भवन के कॉरिडोर में धर्मेन्द्र प्रधान और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बीच मुलाकात हुई थी। पुराने दिन को याद करते हुए धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि जयराम रमेश ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नर्स की तारीफ की थी और मैं इन्हें हँदते हुए एआईसीसी दफ्तर चला गया था। फिर ये कॉमर्स मिनिस्टर बने और मैं सांसद बना मैं इनके ऑफिस में अपने इलाके की मिर्ची के मुंहे पर मिला लाता था।

सरकारें जनता की आवाज सुनें

आज भी बापू का अहिंसा का रास्ता सबसे प्रासंगिक-सोनम

नई दिल्ली/ एजेंसी

अस्पताल से छुट्टी मिलते ही सोनम वांगचुक सीधे राजघाट पहुंचे। 26 दिनों के कड़े अनशन और मेदांता में चले इलाज के बाद, राष्ट्रीता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देना उनकी पहली प्राथमिकता रही। बापू को नमन करते हुए उन्होंने देश को संदेश दिया कि आज भी सत्य और अहिंसा का रास्ता ही सबसे कारगर है। वांगचुक का कहना था कि एक सशक्त लोकतंत्र वही है जहाँ सरकारें जन-आवाज़ का सम्मान करें और हर गतिरोध को बातचीत के जरिए सुलझाएँ। इससे पहले एक्टिविस्ट



सोनम वांगचुक ने कहा था कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल रही है और लद्दाख लौटने से पहले वे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट जाएंगे। एक्स पर एक पोस्ट में वांगचुक ने कहा कि वे सबसे पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को

श्रद्धांजलि देंगे। उन्होंने याद दिलाया कि स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद जंतर-मंतर पर अपना अनशन शुरू करने से पहले भी उन्होंने ऐसा ही किया था। उन्होंने कहा कि आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मुझे इस अस्पताल से छुट्टी मिल रही है। अपने अभियान की शुरुआत को याद करते हुए वांगचुक ने कहा कि आपको शायद याद होगा कि इसी तरह, जब मैं स्विट्जरलैंड से लौटा था, तो अनशन शुरू करने से पहले हमने राजघाट पर श्रद्धांजलि दी थी और फिर जंतर-मंतर गए थे। आज हम फिर वैसे ही करेंगे और उसके बाद लद्दाख में अपने घर के लिए निकलेंगे।

पति से अधिक आय होने पर महिला को अंतरिम गुजारा-भत्ता नहीं

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अमेरिका में रह रही एक महिला को अंतरिम गुजारा-भत्ता (मेंटेनेंस) की मांग खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जब पत्नी की आय पति से अधिक है, तब केवल विदेश में रहने का अधिक खर्च अंतरिम भरण-पोषण का आधार नहीं बन सकता। न्यायमूर्ति भारती डंगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने महिला की उस याचिका को अस्वीकार कर दिया, जिसमें उसने अपने पति से प्रति माह एक लाख रुपये अंतरिम भरण-पोषण की मांग की थी। अदालत ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार महिला को मासिक आय लगभग 8 लाख रुपये (8,700 अमेरिकी डॉलर) है।

नीट विवाद पर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, छात्रों से माफ़ी मांगें प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक विवाद और छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के लिए सार्वजनिक माफ़ी की मांग की है। कांग्रेस महासचिव केशी वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगा और सरकार से जवाब मांगेगा। केरल के अलप्पुझा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान वेणुगोपाल ने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं थी। उनका कहना था कि छात्रों को अपनी मांग रखने का अधिकार है और उनकी आवाज सुनने के बजाय उन पर कार्रवाई करना उचित नहीं है।

ईडी की याचिका पर मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने गांधी परिवार को दिया तीन हफ्ते का समय...

नई दिल्ली/ एजेंसी

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरे प्रतिवादियों को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया। ट्रायल कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर सज़ान लेने से इनकार कर दिया था। सिस्टिंस मनोज जैन ने कहा कि मामले की सुनवाई 10 सितंबर को होगी। गांधी परिवार के अलावा, ईडी की याचिका पर सुमन दुबे,



सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किए गए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम आज इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। आज दो और मामले हैं जिनका समय तय है। आज का

कामकाज का बोझ ज्यादा है। प्रतिवादियों के सीनियर वकील ने ईडी की याचिका का जवाब देने के लिए समय मांगा। श्रद्ध की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती की है और बताया कि दो महीने पहले समय दिए जाने के बावजूद अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। उन्होंने तर्क दिया, यह पूरी तरह से कानून का सवाल है। जवाब दाखिल करने के लिए दो महीने पहले समय दिया गया था। मैं जवाब दाखिल करने पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। यह पूरी तरह से कानून का सवाल है।

डोमाहरी में तीन बच्चियों की जांच पॉजिटिव

कांकेर में दो छात्रों की मलेरिया से हुई मौत स्वास्थ्य विभाग ने जारी की मेडिकल रिपोर्ट

रायपुर। उत्तर बस्तर कांकेर जिले में मलेरिया से संबंधित दो मृत्यु के मामलों के संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने विस्तृत जानकारी जारी की है। विभाग के अनुसार दोनों मामलों में बच्चों की जांच, उपचार, रेफरल और संबंधित क्षेत्रों में मलेरिया जांच की कार्रवाई की गई। 22 जुलाई को चलाए गए मलेरिया मुक्त अभियान के अंतर्गत दोनों संबंधित क्षेत्रों में जांच के दौरान रिपोर्ट निगेटिव पाई गई थी। सुभाष कुमेटी (उम्र 10 वर्ष), ग्राम डुडेराल, विकासखंड केशकाल, जिला कोंडागांव, बालक आश्रम मर्दापोटी में रहकर अध्ययनरत था। आश्रम के दो बच्चों की तबीयत खराब होने पर 21 जुलाई को उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया, जहां आरडी किट जांच में पीएफ़भार पाया गया और चिकित्सक द्वारा एसीटी एवं



प्राइमाक्रोन की पहली खुराक दी गई। 22 जुलाई को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आश्रम के 46 बच्चों की जांच की, जिसमें दो अन्य बच्चों की रिपोर्ट पीएफ़भार पॉजिटिव पाई गई और उन्हें मलेरिया की दवा दी गई। आरएफ़एस के दौरान सुभाष की जांच निगेटिव पाई गई। 24 जुलाई को सुभाष को पुनः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजा गया, जहां जांच पीएफ़भार पॉजिटिव आई।

उपचार की पहली खुराक देने के बाद शेष दवा आश्रम अधिकृत को दी गई। 25 जुलाई की सुबह बच्चों के परिजन उसे अपने साथ गृहग्राम डुडेराल ले गए। अगले दिन सुबह 3 बजे उसकी तबीयत खराब होने पर उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल कांकेर में भर्ती कराया गया, जहां 26 जुलाई की सुबह उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे प्रकरण में ग्राम डोमाहरी, विकासखंड कांकेर निवासी तीजाराम विश्वकर्मा अपनी तीन बेटियों—रवीना विश्वकर्मा (11 वर्ष), सलीना (5 वर्ष) एवं करीना विश्वकर्मा (9 वर्ष)—को बुखार की शिकायत पर 23 जुलाई को आयुष्मान आरोग्य मंदिर डोमाहरी लेकर गए। आरडी किट जांच में तीनों बच्चियों को पीएफ़भार पॉजिटिव पाया गया। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा एसीटी एवं प्राइमाक्रोन की पहली खुराक दी गई।

पुलिस बोली-जानवर बन गए थे सभी

ताहिर हुसैन और चार दोषियों को फांसी हो

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की। पुलिस ने अदालत में कहा कि दोषियों ने पीड़ित पर लगातार हमला करते हुए 'जानवरों के स्तर तक गिरकर' अपराध किया। यह दलील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह के समक्ष दी गई। दोषियों की सजा पर कड़क-डूढ़मा कोर्ट में बहस हुई और अब 31 जुलाई को फैसला आएगा। विशेष लोक



अभियोजक मधुकर पांडे ने अदालत को बताया कि अंकित शर्मा का अपहरण कर बेरहमी से हत्या हुई। दोषियों ने उनकी मृत्यु के बाद भी यातना देना जारी रखा। शर्मा के शरीर पर 51 घाव मिले, जिनमें से 18 नुक़ीले हथियारों से थे।



नीति ने उन्हें जनता के निशाने पर ला खड़ा किया है। जनता की नाराजगी का मुख्य कारण गाड़ियों को होने वाला नुकसान और गिरता माइलेज है। नागरिकों का आरोप है कि एथनॉल मिश्रित पेट्रोल के

कारण पुरानी गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। ARAI की एक रिपोर्ट के अनुसार, ई20 ईंधन पुराने वाहनों के रबर के हिस्सों को खराब कर सकता है और इससे ईंधन की खपत 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। कुछ सर्वे तो यहां तक दावा करते हैं कि माइलेज में 10 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। अभिजीत दीपके ने इसे सरकार की निंजा टेक्निक कहा है, जिसमें पेट्रोल में सस्ता एथनॉल मिलाया जा रहा है, लेकिन पेट्रोल

की कीमतें कम नहीं की जा रही हैं। दीपके के अनुसार, उनके पिता की गाड़ी के इंजन में भी एथनॉल के कारण खराबी आई, जिसका खर्च 40,000 आया। गडकरी पर सबसे गंभीर आरोप हितों के टकराव का लग रहा है। चूंकि गडकरी खुद शुगर मिल्स और एथनॉल उत्पादन से जुड़े रहे हैं, इसलिए आलोचकों का कहना है कि लोगों की गाड़ियां खराब कर वे अपनी फैक्ट्रियों के लिए मुनाफ़ कमा रहे हैं।

नई दिल्ली/ एजेंसी

नीट पेपर लीक विवाद के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे को कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केवल पहली विकेट करार दिया था। अब राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज है कि दीपके की अगली विकेट कौन होगा? इस रेस में वर्तमान में सबसे ऊपर नाम आ रहा है भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय सड़क

परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी की छवि पिछले वर्ष तक एक ऐसे विकास पुरुष की थी, जिनकी तारीफ विपक्षी नेता भी करते नहीं थकते थे। देश भर में फ्लाइओवरों और सड़कों का जाल बिछाने के लिए मशहूर गडकरी, क्रस्स के गढ़ नागपुर से आते हैं और सरसंघचालक मोहन भागवत के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन बीते कुछ समय से पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिलाने की उनकी



पशुपालकों और सरपंचों को मवेशियों को सड़क पर न छोड़ने की अपील

सड़क सुरक्षा को लेकर रायगढ़ यातायात पुलिस को पहल : हाईवे पर ट्रैफ़िक पुलिस ने मवेशियों के गले में लगाए रेडियम बैंड,पुलिस मित्रों को मवेशियों के गले में लगाने रेडियम कालर बेल्ट का वितरण, बरसात में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए शुरू अभियान

रायगढ़ /मूक पत्रिका

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशन में सड़क सुरक्षा को लेकर रायगढ़ यातायात पुलिस द्वारा एक अभिनव एवं जनहितकारी अभियान चलाया गया। ट्रैफ़िक डीएसपी श्री उत्तम प्रताप सिंह तथा प्रभारी यातायात निरीक्षक रोहित बंजारे के नेतृत्व में कल रायगढ़-खरसिया राष्ट्रीय राजमार्ग-49 पर सड़क और सड़क किनारे घूम रहे घुमंतू एवं आवारा मवेशियों के गले में रेडियम रिफ्लेक्टिव टेप बैंड लगाए गए तथा पशुपालकों और पुलिस मित्रों को मवेशियों के गले में रेडियम पट्टे लगाने वितरण किया गया है। इस अभियान के तहत



आज भी यातायात पुलिस द्वारा कोतरगोड़ क्षेत्र में घुमंतू मवेशियों को रेडियम पट्टे लगाए गए।बरसात के मौसम में मवेशी अक्सर हाईवे, सड़कों पर बैठ जाते हैं या अचानक सड़क पार करने लगते हैं। रात के समय कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों को वे समय पर दिखाई नहीं देते, जिससे गंभीर सड़क दुर्घटनाएँ होने की आशंका बनी रहती है। इसी जोखिम को कम करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा यह विशेष अभियान चलाया गया। रेडियम बैंड वाहनों की हेडलाइट पड़ते ही दूर से चमकते हैं, जिससे चालक समय रहते मवेशियों को देखकर वाहन की गति नियंत्रित कर सकते हैं

और दुर्घटनाओं से बचाव संभव हो पाता है।अभियान के दौरान हाईवे किनारे बसे गांवों के सरपंचों, जनप्रतिनिधियों एवं पशुपालकों से भी यातायात पुलिस ने संवाद किया। उन्हें अपने-अपने गांवों के मवेशियों के गले में रेडियम पट्टे लगाने, मवेशियों को खुले में सड़क पर नहीं छोड़ने तथा उनके लिए घर अथवा गौठान में चारा-पानी की समुचित व्यवस्था करने की समझाइश दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि सड़क सुरक्षा को प्रभावी बनाने में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने मवेशियों को राष्ट्रीय राजमार्ग

स्वस्थ बेटियाँ, सशक्त भविष्य की ओर कदम

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामभांठा में छात्राओं को लगाया गया एचपीवी टीका

रायगढ़ /मूक पत्रिका

किशोरियों को सर्वाइकल कैसर (गर्भाशय ग्रीवा कैंसर) जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामभांठा में एचपीवी टीकाकरण अभियान का सफल आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत निर्धारित आयु वर्ग की छात्राओं को एचपीवी वैक्सीन लगाई गई तथा उन्हें टीकाकरण के महत्व, इसके लाभ एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी भी प्रदान की गई।कार्यक्रम के दौरान प्रभारी प्राचार्य श्री नरेन्द्र कुमार पटेल ने स्वास्थ्य विभाग की टीम का स्वागत करते हुए कहा कि किशोरियों का स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य विद्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने छात्राओं एवं अभिभावकों को एचपीवी टीकाकरण के महत्व से अवगत कराते हुए बताया कि यह टीका भविष्य में सर्वाइकल कैसर से



बचाव का प्रभावी माध्यम है। श्री पटेल ने सभी पात्र छात्राओं से बिना किसी संकोच के टीकाकरण कराने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने तथा शासन की जनहितकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम के प्रति विद्यालय परिवार की ओर से आभार भी व्यक्त किया।टीकाकरण कार्य स्वास्थ्य विभाग की एएनएम श्रीमती रजनी चौधरी एवं मितानिन श्रीमती शकुंतला टोण्डे द्वारा सफ़लतापूर्वक संपन्न कराया गया। दोनों ने छात्राओं को टीकाकरण से जुड़ी आवश्यकताएं, संभाषित लाभों तथा स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारीयों भी दीं।

खरसिया: प्रद्युम शर्मा मौत मामले में 1 माह बाद भी न्याय नहीं, पीड़ित परिवार ने कलेक्टर जनदर्शन में लगाई गुहार

रायगढ़/खरसिया/मूक पत्रिका

खरसिया सिविल अस्पताल में कथित चिकित्सीय लापरवाही से हुई युवक प्रद्युम (तामेश्वर) शर्मा की मौत के मामले में एक माह बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाया गया है। परिवार का कहना है कि अब तक उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक उपलब्ध नहीं कराई गई है और दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी मांग को लेकर सोमवार को मृतक के परिजन रायगढ़ कलेक्टर के जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराने तथा दोषी

खरसिया तामेश्वर शर्मा (प्रद्युम) को न्याय दिलाने की गुहार जिला कलेक्टर रायगढ़ को जन दर्शन में लगाई फरियाद



चिकित्सकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की।पीड़ित परिवार का आरोप है कि इलाज के दौरान हुई लापरवाही के कारण प्रद्युम शर्मा की मौत हुई, लेकिन अब तक मामले में न्याय नहीं मिला। इस दौरान मृतक की मां मीडिया से बातचीत करते हुए

रायगढ़ /मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। धरमजगगढ़ वन मंडल के कापू रेंज में दो रात के भीतर हाथियों ने 7 ग्रामीणों के कच्चे मकानों की दीवारें तोड़ दीं और कई किसानों की धान की फसलों को रौंदकर नुकसान पहुंचाया। वहीं घरघोड़ा रेंज में एक हाथी ने स्कूल की बाड़ेंझीवाल भी गिरा दी। घटना के बाद वन विभाग की टीम नुकसान का आकलन करने में जुटी हुई है।जानकारी के अनुसार, शुक्रवार-शनिवार की रात कापू रेंज के जंगल से निकलकर तीन हाथी अलोला गांव पहुंचे। यहां उन्होंने किसान संतोष की धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद बसंती बाई, रामकुमार, लक्ष्मणराम,



जगरसाय, शिवा चौहान, समोतिराम और घुरसाय के कच्चे मकानों की दीवारें तोड़ दीं।हाथियों के गांव में पहुंचने की जानकारी मिलते ही ग्रामीण घरों से बाहर निकल आए और सुरक्षित स्थानों पर चले गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।

कन्हारपुरी नदी किनारे पुलिस की बड़ी दबिश: जुआ फड़ से 09 जुआरी गिरफ्तार, नकद व 07 मोटरसाइकिलें ज़ब्त

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/-उत्तर बस्तर कांकेर जिले में अवैध जुआ, सट्टा एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना कोरर पुलिस ने कन्हारपुरी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए नदी किनारे चल रहे जुआ फ़ड़ पर दबिश दी और 09 जुआरियों को रो हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हुई कार्रवाई पुलिस अधीक्षक निखिल रखेचा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मोहसिन खान के पर्यवेक्षण में असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 27 जुलाई 2026 को ग़प्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम



कन्हारपुरी स्थित नदी किनारे कोसुम पेड़ के नीचे कुछ लोग पैसों का दांव लगाकर -काट पत्ती- नामक जुआ खेल रहे हैं।सूचना मिलते ही थाना कोरर पुलिस की टीम ने गवाहों को साथ लेकर बताए गए स्थान पर योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर दबिश दी। पुलिस को देखकर जुआ खेल रहे लोग भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए मौके से ही 09 आरोपियों को धर दबोचा। जुआ फ़ड़ से ज़ब्ती और कानूनी कार्रवाई पूछताछ और तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे एवं फ़ड़ से ₹11,400 नगद, 52 ताश की पत्तियां, एक ग्रीन

नेट का टुकड़ा, 2 अधजली मोमबत्तियां तथा मौके पर खड़ी 07 मोटरसाइकिलें विधिवत ज़ब्त कीं।

आरोपियों का यह कृत्य छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 की धारा 3(2) के अंतर्गत अपराध पाए जाने पर थाना कोरर में अपराध पंजीबद्ध कर सभी 09 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।गिरफ्तार आरोपियगंगाम निषाद (55 वर्ष), ग्राम गौर गांव, हेमंत साहू (32 वर्ष), ग्राम ज्ञानपेटोली वेदप्रकाश (26 वर्ष), ग्राम कन्हारपुरी, खिलेगा उर्फ खिलानन नायक (26 वर्ष), ग्राम कन्हारपुरी, महेश बघेल (38 वर्ष), ग्राम आयरभाटा।

एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का संदेश

=हर संदिग्ध मृत्यु की रायगढ़ पुलिस वैज्ञानिक और तथ्यपरक तरीके से जांच करती है। अपराधी कानून से बच नहीं सकता। इस मामले में पुलिस टीम ने सूक्ष्म विवेचना, साक्ष्यों के विश्लेषण और प्रभावी पूछताछ से हत्या के पीछे की साजिश का पर्दाफाश किया।=-

पति के शराबखोरी और जमीन मुआवजे की रकम को उड़ाने से नाराज पत्नी ने की हत्या, हत्या को आत्महत्या का रूप देने की साजिश नाकाम

रायगढ़ /मूक पत्रिका

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में पूंजीपथरा पुलिस से ग्राम तराईपाल के धनवारपारा स्थित किराए के मकान में मिले 50 वर्षीय गनपती लाल भगत के शव के मामले में महज 48 घंटे के भीतर सनसनीखेज अंधे कल्ल का खुलासा कर दिया। प्रारंभिक तौर पर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत प्रतीत होने वाले इस मामले में पुलिस ने गहन विवेचना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर हत्या की साजिश का पर्दाफाश करते हुए मृतक की पत्नी तथा दो विधि से संघर्षरत अपराधी बालकों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। मामला मृतक के शराबखोरी और जमीन मुआवजा में मिले रकम को लगातार शराब में खर्च करने को लेकर सामने आया है ।

जानकारी अनुसार दिनांक 25 जुलाई 2026 को मृतक के दमाद सोनसाय उरांव (27 साल) ने थाना पूंजीपथरा में सूचना दी कि उसके ससुर



गनपती लाल भगत (50 साल) का शव किराए के कमरे में तख्त पर पड़ा है। शव के गले में साड़ी जैसा कपड़ा बंधा था तथा बाएं हाथ की कलाई पर कटने के निशान थे। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई की तथा पोस्टमार्टम कराया। घटनास्थल और परिस्थितियों को देखते हुए मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिस पर पुलिस ने हत्या की आशंका के आधार पर गहन जांच शुरू की। मृतक के शर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी हत्या की पुष्टि हुई। जांच के दौरान

पुलिस को मृतक के परिवार पर संदेह हुआ। मृतक की पत्नी गंगाबाई भगत से सघन पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि करीब एक साल पहले पैंत्रिक जमीन गारे पेलमा माइंस में अधिग्रहण होने पर बटवारे में 25-30 साल रूपये इसके पति को बटवारे में मिला था जिसे धीरे-धीरे का शराब में उड़ा रहा था, मांगने पर विवाद करता था । 23 जुलाई 2026 की सुबह गनपती लाल भगत शराब के नशे में घर पहुंचा

और पत्नी तथा बच्चों के साथ मारपीट करने लगा। वषों से घरेलू हिंसा, प्रताड़ना और गारे-पेलमा कंपनी में मुआवजा रकम को लगातार निकाल कर उड़ा रहा था जिससे परेशान होकर गुस्से में गंगाबाई तथा दो अन्य आरोपित ने मिलकर साड़ी और गमछे से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने और घटना को आत्महत्या दर्शाने के उद्देश्य से ब्लेड से मृतक की बाईं कलाई की नस काटी गई तथा उस पर कपड़ा ढंक दिया गया।



पूछताछ में मिले तथ्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपिया गंगाबाई भगत (45 वर्ष) एवं दो विधि से संघर्षरत अपराधी बालकों के विरुद्ध धारा 103(1), 238 एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता (इन्ह्स) के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह एडिशनल एसपी श्री अनिल सोनी तथा डीएसपी श्री सुराशोते बनर्जी के मार्गदर्शन में इस अंधे कल्ल के सफल

संपादकीय

नीट 2026 के प्रश्नपत्र लीक होने के बाद अब यह मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि सरकार को कई स्तर पर स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ रही है। किसी भी मसले पर सरकार के रुख की वजह से अगर जनता या उसके एक हिस्से के बीच असंतोष फैलता है, तो उसका हल निकालना सरकार का ही दायित्व है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए अगर यह कहा कि प्रश्नपत्र लीक के दोषियों को

सजा दिलाने के लिए सरकार ने त्वरित अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, तो यह वक्त का तकाजा है।मगर सदिच्छाओं से ही अगर समस्याओं का समाधान निकल पाता, तो आज देश में बड़ी तादाद में युवाओं के सामने शायद सड़क पर उतरने की नौबत नहीं आती। निश्चित तौर पर नीट 2026 के प्रश्नपत्र लीक होने और इसकी वजह से

नीट पेपर लीक के बाद उठे सवाल- क्या सिर्फ आश्वासन से लौटेगा युवाओं का भरोसा?

समूची परीक्षा का रद्द होना विद्यार्थियों के बीच असंतोष भड़कने का तात्कालिक कारण बना है, लेकिन सवाल है कि क्या यह प्रश्नपत्र लीक होने का कोई पहला मामला था! ऐसा क्यों है कि देश भर में इससे उपजे आंदोलन और उसमें पुलिस कार्रवाई के रुख को लेकर तीखे सवाल उठे हैं और इसके बावजूद सरकार को किसी की जिम्मेदारी तय करना जरूरी नहीं लगता।प्रदर्शनकारियों की एक बुनियादी मांग है कि इसके लिए केंद्रीय शिक्षा

मंत्री से इस्तीफा लिया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार की नजर में इस सवाल की कोई अहमियत नहीं है। वरना क्या वजह है कि इस मुद्दे पर देश के अन्य हिस्सों में भी आंदोलन का दायरा फैलने के बावजूद सरकार अब तक कोई ठोस कार्रवाई करती नहीं दिखी है। यह एक बड़ा कारण हो सकता है कि विद्यार्थियों के एक बड़े तबके के बीच सरकार की कथनी पर भरोसा नहीं बन पा रहा है।सच यह है कि पिछले कई वर्षों से अक्सर

किसी न किसी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले सामने आते रहे और अगर किसी घटना ने तूल पकड़ लिया, तो सरकार की ओर से सबसे पहली कार्रवाई परीक्षा को रद्द करने की हुई। मगर न तो परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी को कठघरे में खड़ा किया गया, न ही संबंधित महकमे के मंत्री से जवाब-तलब किया गया। विपक्ष के एक आरोप के मुताबिक, वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक

गठबंधन के सत्ता में आने के बाद से अब तक 152 प्रश्नपत्र लीक हो चुके हैं और इससे करीब साढ़े सात करोड़ विद्यार्थी प्रभावित हुए।ऐसे में अगर प्रदर्शनकारियों से लेकर विपक्षी दलों की ओर से भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो यह अनायास नहीं है। नीट 2026 के प्रश्नपत्र लीक होने के बाद अब यह मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि सरकार को कई स्तर पर स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ रही है।

प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण का अनूठा संगम है नंदनवन जंगल सफारी

320.15 हेक्टेयर में फैला नंदनवन जंगल सफारी बना प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों का पसंदीदा केंद्र.



धनंजय राठौर

नंदनवन जंगल सफारी नवौं रायपुर में पर्यटकों के लिए कई प्रकार की रोमांचक सफारी राइड्स उपलब्ध हैं, जिनमें शाकाहारी सफारी, टाइगर सफारी, भालू सफारी और लायन सफारी प्रमुख हैं। इसके अलावा यहाँ एक छोटा चिड़ियाघर (नंदनवन जू) भी है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर (अटल नगर) के सेक्टर-39 में स्थित नंदनवन जंगल सफारी राज्य के प्रमुख पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण केंद्रों में शामिल है। 320.15 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह विशाल परिसर प्रकृति प्रेमियों, वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहां वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ पर्यटकों को प्राकृतिक वातावरण में वन्यजीवों को देखने और उनके बारे में जानने का अवसर मिलता है।

मिनी जू से जंगल सफारी तक का सफर

नंदनवन की शुरुआत वर्ष 1979 में रायपुर में ‘नंदनवन मिनी जू’ के रूप में हुई थी। यह वन्यजीवों के रेस्क्यू और राहत केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। वर्ष 2008 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) ने इसे आधिकारिक रूप से ‘मिनी जू’ की मान्यता दी। इसके बाद नवा रायपुर में आधुनिक और विशाल जंगल सफारी विकसित करने के लिए वर्ष 2012 से 2015 के बीच 320.15 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। 1 नवंबर 2016 को छत्तीसगढ़ राज्य के 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नंदनवन जंगल सफारी का उद्घाटन किया।

वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा पर विशेष जोर

नंदनवन जंगल सफारी का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों का संरक्षण, दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण एवं प्रजनन और लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यहां वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप सुरक्षित और तनावमुक्त आवास उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।

विद्यार्थियों और पर्यटकों को वन्यजीवों तथा जैव विविधता के महत्व की जानकारी देने के लिए यहां विभिन्न पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

पांच प्रमुख सफारी जोन हैं आकर्षण का केंद्र

नंदनवन जंगल सफारी को वन्यजीवों की सुरक्षा और पर्यटकों



की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग जोन में विकसित किया गया है।

शाकाहारी सफारी

30.89 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस जोन में चीतल, सांभर, नीलगाय और काला हिरण जैसे वन्यजीव प्राकृतिक वातावरण में विचरण करते हैं।

भालू सफारी

20.03 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित भालू सफारी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहां भालुओं को प्राकृतिक वातावरण में देखने का अवसर मिलता है।



बाघ सफारी

20.04 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली बाघ सफारी में पर्यटक देश के राष्ट्रीय पशु बाघ को करीब से देखने का रोमांचक अनुभव प्राप्त करते हैं।

सिंह सफारी

20.01 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित सिंह सफारी में एशियाई शेरों का संरक्षण किया जा रहा है।

जू जोन

50 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले जू जोन में विभिन्न प्रजातियों के पक्षी, सरीसृप और अन्य वन्यजीव आकर्षण का केंद्र हैं।

दुर्लभ और विशेष वन्यजीवों का भी संरक्षण

नंदनवन जंगल सफारी में विभिन्न चिड़ियाघरों के साथ पशु विनिमय कार्यक्रम के माध्यम से कई दुर्लभ और विशेष वन्यजीवों को लाया गया है। यहां सफेद बाघ, दरियाई घोड़ा, घड़ियाल और



क्लोन जंगली भैंसा ‘दीपाशा’ जैसे वन्यजीव पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण हैं।

देश-विदेश से पहुंचते हैं पर्यटक

वनमंडलाधिकारी श्री थेजस शेखर ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विश्णु देव साय के नेतृत्व और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केंदार कश्यप की मंशानुरूप नंदनवन जंगल सफारी पर्यटकों के बीच लगातार लोकप्रिय हो रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2018-19 में ही देश-विदेश से 1 लाख 74 हजार 611, वर्ष 2019-20 में 1 लाख 60 हजार 767 ,वर्ष 2020-21 में 1 लाख 60 हजार 32, वर्ष 2021-22 में 1 लाख 73 हजार 72, वर्ष 2022-23 में 2 लाख 77 हजार 881, वर्ष 2023-24 में 2 लाख 62 हजार 486, वर्ष 2024-25 में 2 लाख 70 हजार 942, वर्ष 2025-26 में 3 लाख 24 हजार 785, से अधिक पर्यटकों ने जंगल सफारी का भ्रमण किया। यह आंकड़ा इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता का केंद्र

नंदनवन जंगल सफारी में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, विश्व बाघ दिवस और वन्यजीव सप्ताह जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन आयोजनों के माध्यम से लोगों, विद्यार्थियों और पर्यटकों को वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है।

रायपुर से आसान पहुंच

नंदनवन जंगल सफारी नवा रायपुर (अटल नगर) के सेक्टर-39 में स्थित है। यह स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, रायपुर से लगभग 15 किलोमीटर और रायपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जंगल सफारी प्रत्येक सोमवार को बंद रहती है।

वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा का ऐसा अनूठा केंद्र

नंदनवन जंगल सफारी आज छत्तीसगढ़ में पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा का ऐसा अग्र्युत केंद्र बन चुका है, जहां प्रकृति के करीब पहुंचकर वन्यजीवों को देखने के साथ-साथ उनके संरक्षण का संदेश भी मिलता है। घ. (लेखक जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ में संयुक्त संचालक है।)

टीवी प्रसारण की भूमिका राष्ट्र निर्माण में अहम

(**डॉ. रमेश ठाकुर**)

भारत में प्रसारण का कलर 25 अप्रैल 1982 में बदला गया। यहीं से रंगीन टीवी की शुरुआत हुई, वरना इससे पहले तक पर्दा सफेद ही था। ये वह वक्त था जब दिल्ली में एशियाई खेलों का महाकुंभ आरंभ होना था। तब तेजी से वैश्विक स्तर पर मांग उठ रही थी कि खेलों का प्रसारण रंगीन पर्दे पर किया जाए।

भारत में ‘राष्ट्रीय प्रसारण दिवस’ प्रत्येक 23 जुलाई को मनाया जाता है। सूचना विधाओं के लिहाज से आज का दिन रेडियो क्रांति और प्रसारण का प्रतीक भी है। दिवस की शुरुआत वर्ष-1927 में हुई थी जिसका आज का 99 वां संस्करण है। सर्वविदित है कि 23 जुलाई 1927 को ‘इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी’ नाम से एक प्राइवेट संस्था ने ‘बॉम्बे रेडियो क्लब’ स्टेशन से हिंदुस्तान में पहला प्रसारण किया गया था जो ब्रिटिश औपनिवेशिक हुकूमत द्वारा लाइसेंस प्राप्त थी। कुछ वर्षों बाद ‘ऑल इंडिया रेडियो’ और फिर आकाशवाणी के रूप में स्थापित हुई। वैसे, विधिवत रूप से प्रसारण मंच का शुभारंभ 8 जून 1936 से हुआ था। इसी दिन से विविध भाषाओं, संस्कृतियों और विचारों को एक सूत्र में पिरोने का चलन आरंभ हुआ। आकाशवाणी का नाम प्रसिद्ध रचनाधर्मी ‘एम्बी गोपालस्वामी’ द्वारा दिया गया था, जो संस्कृत शब्द से गढ़ा गया था। जिसका शाब्दिक मतलब होता है ‘आकाश से आवाज’। इस शब्द को आधिकारिक रूप से 1935 में मैसूर में भारत के पहले निजी रेडियो स्टेशन की स्थापना के वक्त इस्तेमाल हुआ, जिसे बाद में भारत सरकार ने सार्वजनिक और आधिकारिक रूप से सरकारी रेडियो के लिए प्रयोग किया। भारतीयवायु सेना भर्ती प्रसार भारती के नाम से प्रचलित भारतीय प्रसारण तंत्र आज विश्व का बससे बड़ा ब्रॉडकास्ट डिजिजन है। 15 सितंबर 1959 को, दिल्ली स्थित ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में, भारत का पहला टीवी चैनल शुरू किया गया था जो आज ‘दूरदर्शन’ यानी डीडी न्यूज के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसारण के विस्तार पर अगर नजर डालें, तो वर्तमान में आकाशवाणी के कुल 591 रेडियो केंद्र और प्रसारण के 230 स्टेशन संचालित हैं। वहीं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में इस समय 908 निजी सैटेलाइट टीवी न्यूज चैनल सार्वजनिक प्रसारण सेवा में हैं। इनमें 40 फीसदी यानी करीब 350-400 के बीच केवल समाचार श्रेणी के हैं, जो हिंदी, अंग्रेजी के अलावा विभिन्न राज्यस्तरीय भाषाओं में संचालित हैं। निजी प्रसारण में आगमन सबसे पहले 1992 में ‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज’

से हुआ, उसके बाद तो निजी क्षेत्र में प्रसारणों की बाढ़ आ गई। करीब 3 हजार से अधिक नए लाइसेंसों के लिए मंत्रालय में आवेदन आवेदित हैं।

भारत में प्रसारण का कलर 25 अप्रैल 1982 में बदला गया। यहीं से रंगीन टीवी की शुरुआत हुई, वरना इससे पहले तक पर्दा सफेद ही था। ये वह वक्त था जब दिल्ली में एशियाई खेलों का महाकुंभ आरंभ होना था। तब तेजी से वैश्विक स्तर पर मांग उठ रही थी कि खेलों का प्रसारण रंगीन पर्दे पर किया जाए। इसके बाद ‘ब्लैक एंड व्हाइट’ के दौर का अंत हुआ और टीवी का पर्दा रातों-रात कलरफुल हो गया। टीवी प्रसारण का मतलब होता है ऑडियो और वीडियो सामग्री को विधुत चुम्बकीय तरंगों जैसे केबल, सैटेलाइट या इंटरनेट के जरिए जन जन तक पहुंचाना। प्रसारण आज के समय में सभी के जीवन का हिस्सा बन गया है। प्रसारण ऐसी संचार प्रणाली है जो दर्शकों को घर बैठे न्यूज से लेकर मनोरंजन के सभी माध्यमों को परोसता है। हालांकि, तकनीकी विकास के साथ प्रसारण विधाओं में काफी बदलाव हुआ है। अब दर्शक केबल या सैटेलाइट यंत्रों पर ही निर्भर नहीं रहते। दर्शक डाटा खर्च करके मोबाइल से ही हर प्रकार के प्रसारण का लुप्त उठा लेते हैं। फिर चाहे, मैच हो या समाचार।

प्रसारण के क्षेत्र में अब इंटरनेट, डिजिटल और ओटीटी ने और विस्तार कर दिया है। सरकार सालाना प्रसारण से विज्ञापनों और फीडिंश से करीब 1200 से 1600 करोड़ रूपए कमाती है। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रसार भारती का कुल राजस्व 1643 करोड़ था जिसमें से प्रमुख हिस्सा सरकारी डीटीएच प्लेटफार्म का था। साल 2025 के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा बताया गया था कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने निजी विज्ञापनों से तीन साल यानी 2022 से 2025 के बीच कुल 587.78 करोड़ कमाए। वहीं, 2025-2026 के अंत तक 650 करोड़ कमाने का लक्ष्य प्रसार भारती ने रखा हुआ है। ये ऐसा लक्ष्य है जिसे भी आसानी से हासिल किया जा सकता है। राष्ट्र निर्माण में प्रसारण की जो स्वर्णिम यात्रा सदियों पहले आरंभ हुई थी वह आज भी निरंतर जारी है। प्रसारण का क्षेत्र जनमानस के मन के तारों को छूता है। प्रसारण के जरिए ही बदलती तकनीकों के साथ संवाद भी निरंतर होता है। केंद्र सरकार ने फी और निशुल्क चैनलों का वर्गीकरण भी बीते कुछ सालों से किया है, ताकि कोई भी दर्शक प्रसारण के रस से अछूता न रहे। ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ ऐसा प्रसारण नारा है ।

घटती नदियां, बढ़ता जल संकट- पानी के कुप्रबंधन की कीमत चुका रहा है भारत

(**अंशुल उपाध्याय**)

आज विश्व की जनसंख्या लगभग आठ अरब है। जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट के बीच पानी की बढ़ती मांग इस समय बड़ी चुनौती बनती जा रही है।

नदियों का घटना जल स्तर गंभीर चिंता का विषय है। यह स्थिति जलवायु परिवर्तन और पानी के अत्यधिक दोहन के कारण पैदा हो रही है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की प्रमुख नदियों के बेसिन की क्षमता तेजी से गिरि है। कुछ प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट आई है। इस श्रेणी में नर्मदा नदी को देखें, तो जबलपुर में इसके जल स्तर में भारी कमी आई है। ख्वारीघाट और बरगी जैसे क्षेत्रों में पानी काफी कम हो गया है। अलग-अलग हिस्सों में पानी का स्तर एक से तीन मीटर तक कम हुआ है, जिससे कई जगहों पर घाट और टापू नजर आने लगे हैं।

दिल्ली और हरियाणा में भी यमुना का जल स्तर अक्सर अपने सामान्य स्तर से नीचे चला जाता है, जिससे जल शोधन संयंत्रों की क्षमता प्रभावित होती है। गर्मियों में भूजल का स्तर लगभग पचास फीसद तक कम हो जाता है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच बहने वाली महानदी का प्रवाह भी अपेक्षाकृत कम हुआ है और इसके बेसिन में भी पानी का स्तर पचास फीसद से भी कम दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों कावेरी और कृष्णा के जल स्तर में पिछले वर्षों की तुलना में भारी गिरावट (लगभग 33 फीसद) दर्ज की गई है। अपर्याप्त वर्षा और अत्यधिक गर्मी के कारण दक्षिणी क्षेत्र के प्रमुख जलाशयों में जल स्तर घटकर उनकी कुल क्षमता का मात्र बीस फीसद रह गया है।

जल स्तर में कमी के कारणों में कम वर्षा और जलवायु परिवर्तन अधिक जिम्मेदार हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि और कम वर्षा के कारण प्राकृतिक जल चक्र

प्रभावित हो रहा है। इससे नदियों को पर्याप्त वर्षा जल नहीं मिल पाता। वहीं बांधों ने भी स्थिति बिगाड़ी है। इससे जलग्रहण क्षेत्र कम हुआ है। दरअसल, नदियों पर अधिक बांध बनाने और जलग्रहण क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई से नदियों का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है।



एक समस्या अनियंत्रित सिंचाई की भी है। गौरतलब है कि कृषि में भारी मात्रा में पानी का उपयोग होता है, जो कई बार नदियों के प्राकृतिक प्रवाह से ही खींच लिया जाता है, जिससे जल स्तर तेजी से गिरता है। वहीं बोरवेल और नलकूपों के माध्यम से अत्यधिक भूजल निकालने के कारण नदियों का प्राकृतिक जलभरण घट जाता है। इससे गर्मी के महीनों में नदियों का पानी सूखने लगता है। कारखानों के लिए नदियों से बड़ी मात्रा में पानी निकाले जाने से भी असर पड़ा है। दूषित पानी वापस छोड़ने से जल की

गुणवत्ता और मात्रा दोनों घटती हैं।

इसके अलावा, पानी का एक वस्तु के रूप में जिस तरह से कारोबार शुरू हुआ है, यह भी चिंता का विषय है। मीठे जल के स्रोतों में भारी कमी के कारण अब पानी को बोतलों और टैंकरों में भरकर बेचा जाने लगा है। मुंबई, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद और



हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में तो पानी बेचना एक आम बात हो गई है। शहरी लोग अपने दैनिक उपयोग के लिए भी पानी खरीदते हैं। पानी को वस्तुओं की श्रेणी में शामिल किया गया है। इससे यह आशंका पैदा हो गई है कि बाजार पानी की कमी के प्रभावों को और बढ़ा सकता है।

शहरों से गुजरने वाली नदियों का पानी अब इतना प्रदूषित हो चुका है कि उसका दैनिक क्रियाकलापों में भी उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि बड़ी नदियों में शहरों का गंदा पानी छोड़ा जाना

भी प्रायोजित प्रतीत होता है, ताकि पानी के व्यापार को बढ़ावा मिल सके।

जिन देशों में मीठे जल के स्रोत नहीं हैं, वहां समझ आता है कि पानी का जल का व्यापार हो। लेकिन भारत जैसे देश में, जहां मीठे जल के पर्याप्त स्रोत रहे हैं, उनमें कमी आना और पानी का बढ़ता कारोबार अपने पीछे कई सवाल खड़े करता है। नदियों को प्रायोजित तरीकों से प्रदूषित किए जाने की आखिर क्या वजह हो सकती है? क्या इसलिए कि लोग नदी के पानी का सीधे इस्तेमाल न कर सकें? मीठे जल की अन्य देशों में अधिक मात्रा में आपूर्ति क्यों की जा रही है? जगह-जगह बोरिंग की इजाजत देने का मतलब है कि इससे भूजल स्तर लगातार कम होता जाएगा। आज विश्व की जनसंख्या लगभग आठ अरब है। जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट के बीच पानी की बढ़ती मांग इस समय बड़ी चुनौती बनती जा रही है। दूसरी ओर, शहरीकरण से पानी की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। दोनों ही जल संकट के प्रमुख कारण हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां जल आपूर्ति अनिश्चित है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2018 में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में जल संकट पैदा हुआ और यह चरम सूखे, खराब जल प्रबंधन तथा अत्यधिक खपत के कारण पीने के पानी की कमी का सामना करने वाला पहला बड़ा शहर बना। चीन में भी पानी की कमी का खतरा मंडा रहा है।

हर साल युद्ध और अन्य प्रकार की हिंसा से होने वाली मौतों से कहीं अधिक लोगों की जान जल प्रदूषण की वजह से जाती है। पृथ्वी के जल का केवल एक फीसद से भी कम हिस्सा हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। इसलिए मानवीय गतिविधियां हमारे जल संसाधनों के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं। जल प्रदूषण के कई स्रोत हैं, जिनमें अपशिष्ट जल खास तौर पर शामिल है। विश्व में अस्सी फीसद से

अधिक अपशिष्ट जल बिना शोधित हुए नदियों में वापस चला जाता है। वहीं कीटनाशक और विषैले रसायन भूजल तथा आसपास के जल स्रोतों में रिस जाते हैं। परिणामस्वरूप, बहुमूल्य जल संसाधन दूषित हो जाते हैं। इससे पीने के पानी की उपलब्धता कम होती जाती है।

कहा जा सकता है कि जलवायु में हो रहे उथल-पुथल के बीच सूखा एक प्राकृतिक घटना है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में एक निश्चित अवधि के लिए शुष्क परिस्थितियां और वर्षा की कमी बनी रहती है। हालांकि वर्षा की मात्रा विभिन्न क्षेत्रों और वर्ष के अलग-अलग समय में स्वाभाविक रूप से भिन्न हो सकती है। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वर्षा के स्वरूप को बदल रहे हैं। बढ़ते तापमान का मतलब है कि मिट्टी में मौजूद नमी तेजी से वाष्पित हो जाती है और भीषण लू चलने से सूखे की स्थिति और बिगड़ जाती है। इससे जल संकट बढ़ता है।

जलवायु परिवर्तन, जल प्रबंधन में गड़बड़ी और अत्यधिक खपत के कारण विश्व के कई हिस्सों में जल संकट उत्पन्न हो रहा है। ये परिस्थितियां अगर लगातार बनी रहें, तो भारत में भी समुद्री जल को शोधित करके पीने की नौबत आ सकती है। जल संकट के दुष्परिणाम खाद्य असुरक्षा से लेकर मानवीय संघर्षों में वृद्धि के रूप में सामने आ सकते हैं। ऐसे में वैश्विक जल संसाधनों के संरक्षण के महत्त्व को समझा जा सकता है। आज पृथ्वी का कोई भी महाद्वीप जल संकट से अछूता नहीं रहा है, विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में। अनुमान है कि आने वाले समय में विश्व की लगभग दो-तिहाई आबादी को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। यह चिंताजनक प्रवृत्ति कई लोगों को यह प्रश्न पूछने पर मजबूर कर रही है कि भविष्य में जल की उपलब्धता की सीमा क्या होगी?

